



31 AUG 2019

**GENERAL STUDIES (Module – 9)**निर्धारित समय: तीन घंटे  
Time allowed: Three Hours

DTVF/19 (N-M)-M-GS19

अधिकतम अंक: 250  
Maximum Marks: 250

Name: Girdhari Lal Meena Mobile Number: \_\_\_\_\_  
Medium (English/Hindi): Hindi Reg. Number: AWAKE-19/E017  
Center & Date: 31/08/2019, Delhi UPSC Roll No. (If allotted): 0856006

**प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश**

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:  
इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं।  
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।

प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

**QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS**

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

There are TWENTY questions printed both in HINDI and ENGLISH.

All the questions are compulsory.

The number of marks carried by a question is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्ता द्वारा भरा जाए (To be filled by Evaluator only)

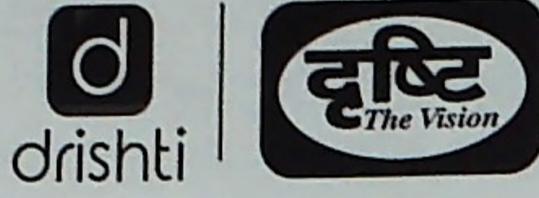
Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.		11.	
2.		12.	
3.		13.	
4.		14.	
5.		15.	
6.		16.	
7.		17.	
8.		18.	
9.		19.	
10.		20.	
Grand Total (सकल योग)			

मूल्यांकनकर्ता (हस्ताक्षर)  
Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्ता (हस्ताक्षर)  
Reviewer (Signature)

www.drishtias.com

Contact: 8750187501, 8448485517



## Feedback

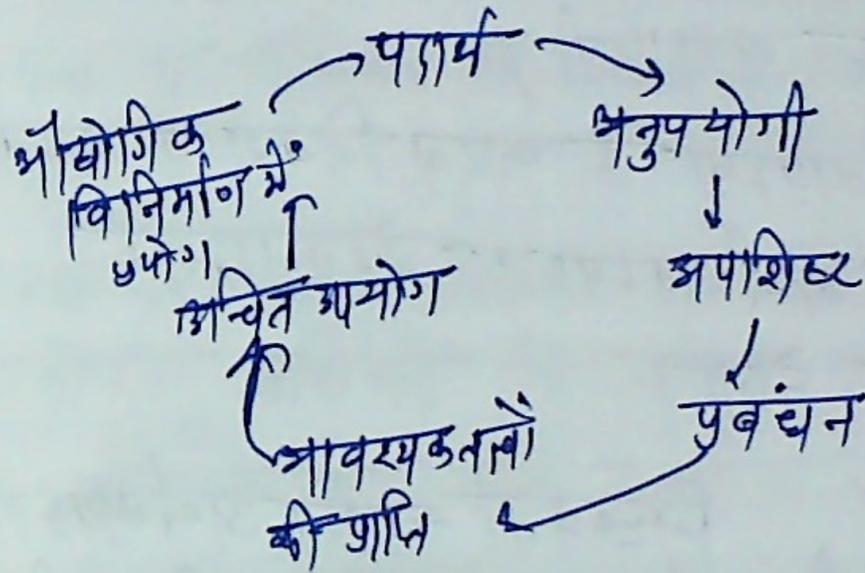
1. Context Proficiency (संदर्भ दक्षता)
  2. Introduction Proficiency (परिचय दक्षता)
  3. Content Proficiency (विषय-वस्तु दक्षता)
  4. Language/Flow (भाषा/प्रवाह)
  5. Conclusion Proficiency (निष्कर्ष दक्षता)
  6. Presentation Proficiency (प्रस्तुति दक्षता)
-

1. चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या है? भारत में चक्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता का उल्लेख कीजिये।  
(150 शब्द) 10

What is circular economy? Highlight the need of circular economy in India.  
(150 words) 10

चक्रीय अर्थव्यवस्था सेवा, विनिर्माण, कृषि क्षेत्र के परस्पर सम्बन्धों को

चक्रीय अर्थव्यवस्था अपशिष्ट व बेकार पदार्थों के पुनर्चक्रण के माध्यम से नवीन पदार्थों के निर्माण की बात करती है (विश्व आर्थिक मंच)



आवश्यकता

① चक्रीय अर्थव्यवस्था के कारण वर्तमान अपशिष्ट पुनर्चक्रण से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा।

② इसके कारण नवीन रोजगार का सृजन होगा।

③ पुनर्चक्रण गतिविधियों में कमी के कारण पर्यावरणीय लक्ष्य भी प्राप्त होगा तथा जलवायु परिवर्तन की समस्या पर नियंत्रण किया जा सकेगा।

④ चक्रीय अर्थव्यवस्था के कारण वर्तमान समुदाय अर्थव्यवस्था पर अपशिष्टों के प्रभाव को कम किया जा सकता है।

⑤ चक्रीय अर्थव्यवस्था रेटिया घड़ित्त में कमी लायेगी तथा इस कारण स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सहायता प्राप्त होगी।

⑥ चक्रीय अर्थव्यवस्था विनमण गतिविधियों के अभाव देने के साथ-साथ मारन को निवृत्त प्रविष्टि राष्ट्र बनाएगी।

⑦ चक्रीय अर्थव्यवस्था के कारण निवेश व तकनीक के माध्यम से अर्थव्यवस्था को बेरचनात्मक परिवर्तन में लगेगा।

निष्कर्षतः चक्रीय अर्थव्यवस्था आर्थिक, पर्यावरणीय व रोजगार की दृष्टि से आवश्यक है अतः इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

2. हाल ही में पारित उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019 के प्रावधानों और महत्त्व का उल्लेख कीजिये।

(150 शब्द) 10

Highlight the provisions and significance of recently passed Consumer Protection Bill 2019.

(150 words) 10

बदलते वैश्विक परिदृश्य व तकनीकी प्रयोग के कारण भारत द्वारा अपने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019 को पारित किया गया।

प्रावधान

① इसके तहत उपभोक्ता को चार अधिकार दिए गए इनमें सूचना का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, चयन का अधिकार व शिकायत का अधिकार शामिल है।

② इस विधेयक के माध्यम से ई-कॉमर्स के तहत उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण की बात की गई।

③ अपील के लिए तीन स्तरीय संरचना का निर्माण किया गया।

केन्द्र → निर्दिष्ट सीमान्तकी

राज्य

जिला → 20 लाख तक के विवाद

④ प्रस्तुत विधेयक में उद्येक बल्त्यानीकरण व विजना के अधिकार के संरक्षण का भी प्रावधान किया गया है।

⑤ प्रस्तुत विधेयक शिकायत व इसके निपटन की डिजिटल व्यवस्था व उपभोक्ताओं के जागरूकता

- लिए भी प्रावधान करता है।  
प्रश्न 6 ई-कॉमर्स को बढ़ावा  
 ③ जागरूक उपभोक्ता का निर्माण  
 ④ शिकायतों का त्वरित निपटान  
 ⑤ निगताडे अधिकार की सुरक्षा  
 ⑥ उपभोक्ता अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में  
 अनुसंधान को प्रोत्साहन।  
 ⑦ प्रैक्टिक वैश्विक प्रक्रियाओं को लागू किया गया।  
 ⑧ शिकायत निपटान की विकेंद्रीकृत व  
 प्रभावी व्यवस्था।

निष्कर्ष: इस निवेदन से संबंधित  
 चुनौतियों के समाधान व किन परिणाम होने  
 वाले अधिनियम का उचित क्रियान्वयन का  
 उपभोक्ता अधिकार को सुरक्षित किया जा  
 सकता है।

उम्मीदवार को इस  
 हाशिये में नहीं लिखना  
 चाहिये।

(Candidate must not  
 write on this margin)

3. नियामक सैंडबॉक्स फिनटेक (वित्तीय तकनीकी) फर्मों को बिना किसी भय के संचालित होने में सहायता प्रदान करेगा। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द) 10

Regulatory sandbox will help fintech firms disrupt without fears. Comment.

फिनटेक फर्म अक्सर नए डिजिटल तकनीकों के  
उपयोग के माध्यम से कार्य करती हैं जिनमें प्रायः  
सूचना प्रबंधन व भुगतान शामिल हैं

वर्तमान में डिजिटल इंडिया  
व ई-कॉमर्स के बढ़ते दायरे के कारण  
फिनटेक फर्मों का कार्य क्षेत्र विस्तृत होता जा  
रहा है। इसके कारण इन पर अधिक नियंत्रण,  
साइबर धोखाधड़ी, डेटा चोरी का भय  
विद्यमान रहता है। फेडरल रेगुलैटरी बॉडी द्वारा इस  
भय को बढ़ा दिया गया।

इस कारण नियामक सैंडबॉक्स  
की आवश्यकता उत्पन्न हुई है-

- ① इसके कारण फिनटेक कंपनियों में पारदर्शिता  
का समावेश होगा तथा समय रहते रोक-कामियों  
को पहचाना जा सकेगा।
- ② नियामक सैंडबॉक्स के कारण डेटा सुरक्षा में  
बृद्धि होगी।
- ③ नियामक सैंडबॉक्स साइबर सुरक्षा के एकीकृत  
व समान ढाँचे के निर्माण में सहायता प्रदान

उम्मीदवार को इस  
हार्शिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

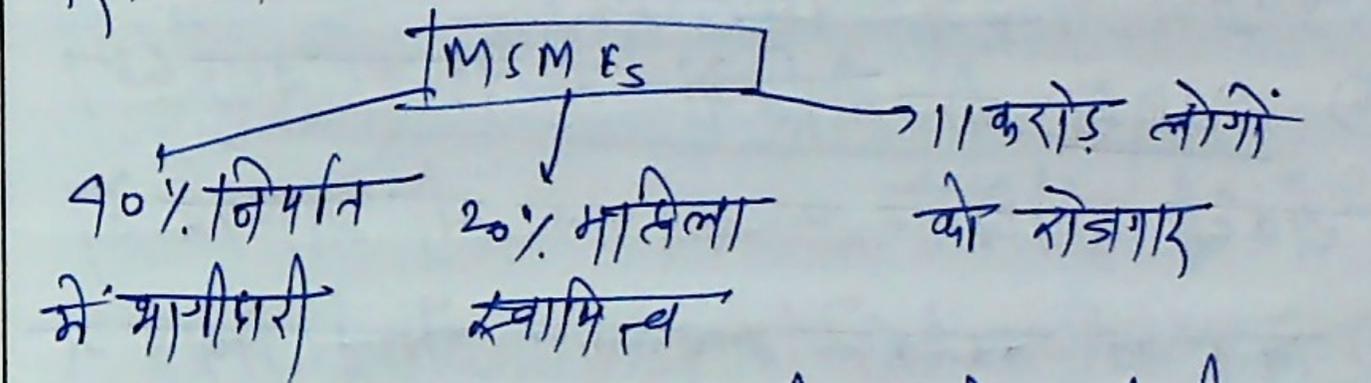
(Candidate must not  
write on this margin)

- कना।
- ④ इसके कारण विदेशी धोखाधड़ी पर नियंत्रण किया जा सकेगा।
- ⑤ निषामक सैडबॉक्स के कारण सरकारी अनुक्रिया में वृद्धि होगी तथा साइबर सुरक्षा के वर्तमान ढाँचे की निरंतरता के साथ समीक्षा की जा सकेगी।
- ⑥ निषामक सैडबॉक्स विशेषी सहयोग के साथ-साथ डेटा स्थानीयकरण के कारण इन कंपनियों के दुरुपयोग की सम्भावना में कमी आयेगी।
- ⑦ इस कारण डिजिटल युगतान एवं डिजिटल धर्मव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
- निष्कर्षतः निषामक सैडबॉक्स व अन्य सुरक्षा उपायों के माध्यम से फिजिकल कंपनियों तथा डिजिटल धर्मव्यवस्था की सुरक्षा की जानी चाहिए।

4. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सामाजिक-आर्थिक विकास में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। व्याख्या कीजिये। इसके अतिरिक्त एम.एस.एम.ई. के पिछड़ेपन को बढ़ावा देने वाली नीतिगत चुनौतियों का उल्लेख कीजिये और आवश्यक उपाय सुझाइये। (150 शब्द) 10

MSMEs play a great role in socio-economic development. Explain. Also, highlight the policy challenges that foster dwarfism of MSMEs and suggest necessary measures. (150 words) 10

MSMEs निवेश के आधार पर 25 करोड़ तक के उद्योगों के रूप में जाने जाते हैं जो विनिर्माण निर्यात निर्यात में प्रभावी भूमिका अदा करते हैं।



→ MSMEs महिला सशक्तिकरण में भागीदारी अदा करते हैं।

→ MSMEs कृषि एवं खादी उद्योग के माध्यम से ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देते हैं।

→ MSMEs रोजगार, निवेश निर्यात के कारण आर्थिक दृष्टि से ही लाभदायक हैं। नीतिगत चुनौतियाँ

① विभिन्न नीतियों यथा SEZ, CEC के कारण इनके मध्यम समय का अभाव।

② GST व्यवस्था के कारण MSMEs में क्रय एवं बिक्री संबंधी सैकट सामने आया है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

③ विभिन्न योजनाओं में समन्वय का अभाव है तथा वे किंग कमजोरी के कारण इनको पर्याप्त ऋण की उपलब्धता नहीं हो रही है।

④ विश्व व्यापार युद्ध के कारण श्री MSMEs की वृद्धि बाधित रही है।

उपाय

① 59 मिनट में ऋण व उद्योगमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन।

② MSMEs की नीतियों में समन्वय तथा 657 संबंधी चुनौतियों का समाधान भी आवश्यक है।

③ विज्ञान एवं तकनीक के साथ-साथ कौशल विकास पर भी बल दिया जाना चाहिए।

④ MSMEs क्षेत्र में कर व नियंत्रण संबंधी मुद्दों में सुसंगतता लाई जानी चाहिए।

निष्कर्ष: भारत में विनिर्माण बढ़ाने, रोजगार व निर्यात को बढ़ावा देने के लिए MSMEs से संबंधित नीतिगत चुनौतियों का समाधान भी आवश्यक है।

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

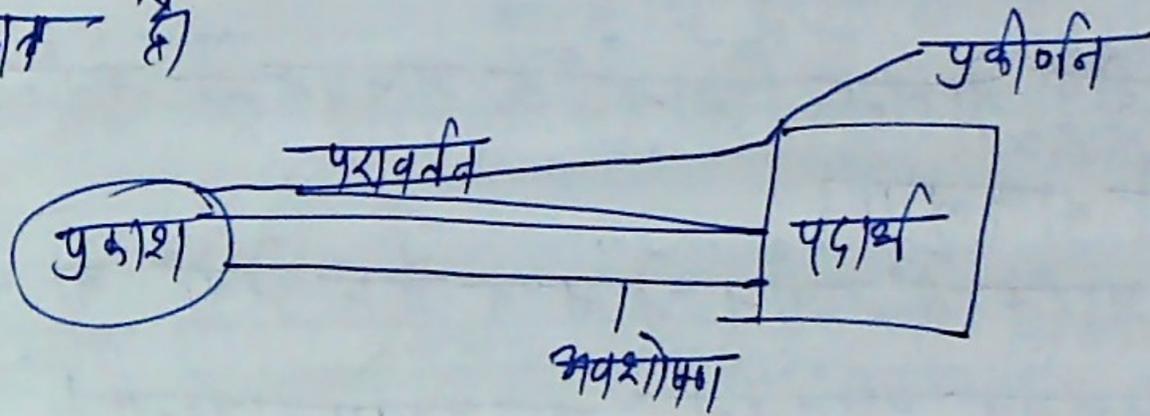
5. प्रो. सी.वी. रमन पहले एशियाई वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। विज्ञान के क्षेत्र में रमन प्रभाव के रूप में उनके योगदान एवं इसकी प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिये। (150 शब्द) 10

Prof. C.V. Raman was the first Asian scientist to be awarded a Nobel Prize. Explain his contribution of Raman Effect to science and its relevance. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

रमन प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन व प्रकाश के अवशोषण के विस्तार पर आधारित है जहाँ परावर्ष की दिशा विशेष तरंगदैर्घ्य के प्रति प्रतिक्रिया हो देखा जाता है।



इस रमन प्रभाव की खोज पानी द्वारा प्रकाश के सभी प्रकीर्णन व परावर्ष के माध्यम पर की गई। इसी कारण 1930 में सर सी. वी. रमन को भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल भी दिया गया।

योगदान

- ① रमन प्रभाव के माध्यम से प्रकाश के नीले रंग व अन्य गुणधर्मों की खोज की गई।
- ② रमन प्रभाव के कारण मौसमी जातिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन सम्भव हुआ।
- ③ रमन प्रभाव का प्रयोग नैनी तकनीक के विकास में भी किया गया।
- ④ रमन प्रभाव के रिमोट से सिंग में भी उपयोग

विद्या जा रहा है  
 ⑥ परगुठी म गुणधर्मों व जल व ऊर्जा स्रोत की पहचान  
 की रमन प्रभाव के आधार पर की जाती है

प्रासंगिकता

① चन्द्रमान के माध्यम से चन्द्रमा की स्थलाकृति,  
 घनत्व की जानकारी।

② डीप प्रोशन मिशन के माध्यम से नीली क्रांति  
 की सफलता।

③ भारत में नवीन तेल व गैस क्षेत्रों की खोज।

④ जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करना।

⑤ ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति के लिए पृथ्वी एवं अन्य  
 ग्रहों के गुणधर्मों में समानता व अक्षमता की  
 स्थापना।

निष्कर्षतः रमन प्रभाव विज्ञान के  
 क्षेत्र में क्रांति की त्रिभुज प्रासंगिकता भूगर्भीय  
 अध्ययन, सुरक्षा व अंतरिक्ष क्षेत्र में बनी हुई है।

उम्मीदवार को इस  
 हाशिये में नहीं लिखना  
 चाहिये।  
 (Candidate must not  
 write on this margin)

6. भारत में हाल ही में हुई अग्नि आपदाओं के संबंध में व्याख्या कीजिये कि देश में ये आपदाएँ निरंतर क्यों घटित हो रही हैं? (150 शब्द) 10

With respect to the recent fire disasters in India, explain why fire accidents are unabated in India. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

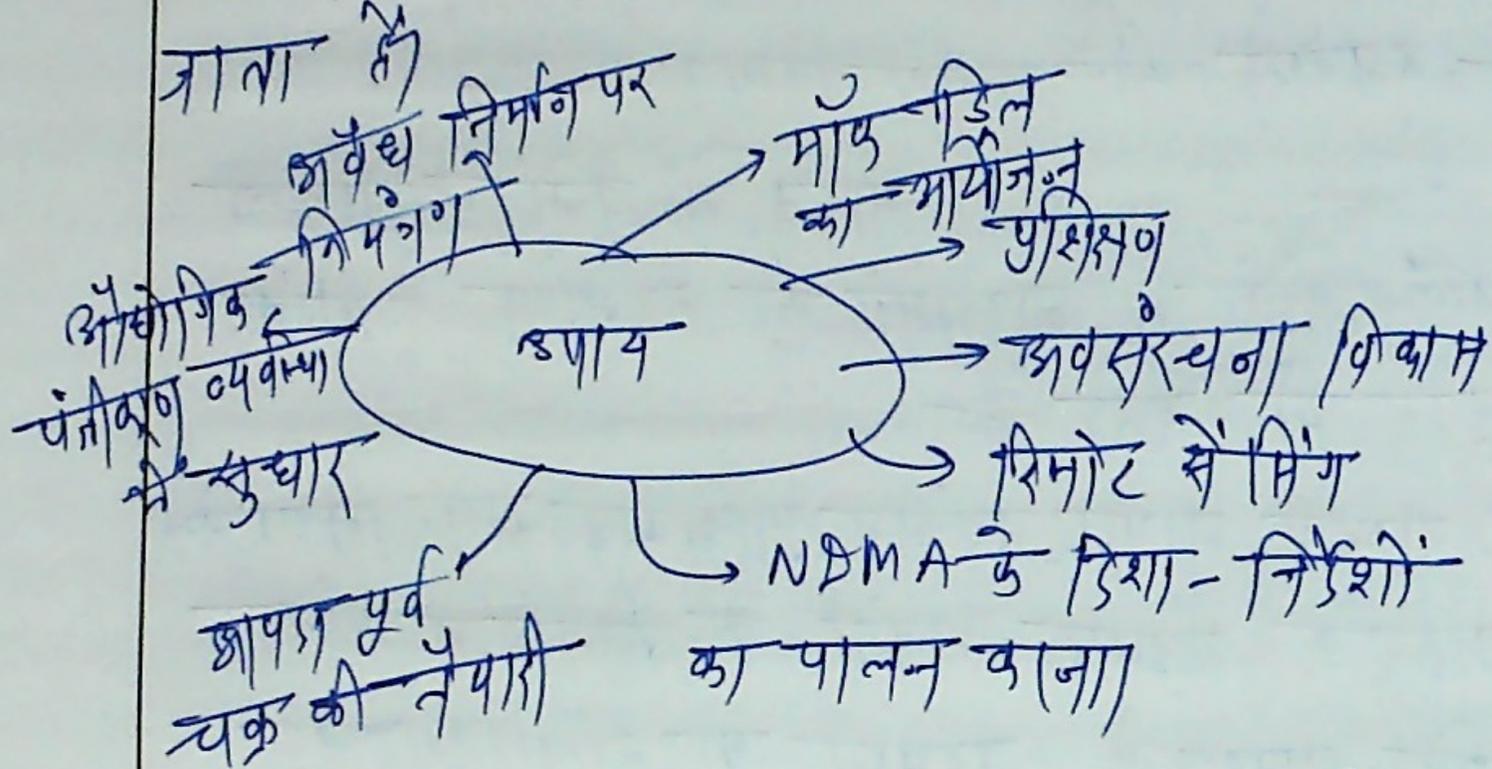
सुरत, दिल्ली एम्स व मुम्बई आग की घटनाओं ने भारत में अग्नि आपदाओं को संबंधित तैपारी की कमजोरी को उजागर किया।

भारत में वनों व विभिन्न अवसंयन्त्रों में आपदाओं की घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है-

- ① राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित आरूप के अनुसार चवनों के निर्माण करने से अग्नि आपदा में नुकसान की सम्भावना बंद जाती है। (सुरत की आग)
- ② आपदा के लिए कर्मचारियों के पास पर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव होता है।
- ③ अग्नि आपदा से निपटने के लिए पर्याप्त अवसंयन्त्रों की पहलूय भी अमुख वाद्या है।
- ④ अतः उत्तराखण्ड के जंगलों में आग मानवीय अस्तित्व के कारण बढ़ती जा रही है।
- ⑤ जलवायु परिवर्तन व बढ़ते तापमान के कारण भी आग की घटनाओं में वृद्धि देखी जा

रही है।

⑥ अग्नि आपदा से संबंधित डिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जाता तथा अग्नि-निर्माण और औद्योगिक-गतिविधियों का परित्याजन किया जाता है।



निष्कर्षतः अग्नि आपदा पर नियंत्रण के लिए सरकारी एजेंसियों के सहयोग के साथ-साथ जनता की जागरूकता भी आवश्यक है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

7. बांध एक वरदान है या अभिशाप? भारत में हाल ही में पारित बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 के अनुरूप इस कथन का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द) 10

Dams are a boon or a bane? Analyze in line with the recently passed Dam Safety Bill 2019 in India. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

~~बांधों से सम्बन्धित समस्याओं व सम्भावनाओं के दोहन के लिए बांध सुरक्षा विधेयक 2019 पारित किया गया।~~

प्रश्न

~~① इस विधेयक में बांध सुरक्षा प्राधिकरण व DRIP (बांध पुनः उद्धार व क्रियान्वयन प्रोजेक्ट) की स्थापना की गई है।~~

~~② बांध सुरक्षा के लिए डिजिटल रूप से प्रयत्न करने के विकास की बात की गई है।~~

~~③ केन्द्र-राज्यों के मध्य समन्वय व बांध प्रबंधन की उन्नित व्यवस्था की स्थापना की गई है।~~

~~④ बांध सुरक्षा के लिए किसी तकनीक व निवेश के लिए भी प्रावधान किया गया है।~~

बांध वरदान

~~① बांधों के कारण जल विद्युत का उत्पादन होता है तो कई विनिर्माण गतिविधियों की कड़ा मिलती है।~~

~~② बांधों के कारण कृषि के लिए जल की उपलब्धता, पेयजल व वर्षा जल संचयन में सहायक होता है।~~

~~③ बांध सुरक्षा विधेयक 2019 के अनुसार बांध उत~~

क्षेत्रों के लिए एक बरदान का कार्य करने हैं क्योंकि  
इससे निवेश व रोजगार के क्षेत्रों में वृद्धि होगी है

अभिशाप

① बांधों की सुरक्षा संबंधी विना को इस विधेयक  
में भी बनाया गया

② बांधों के कारण राज्यों के मुख्य विवादों  
के भी वहावा मिलता है। कर्नाटक-तमिलनाडु,  
कर्नाटक - महाराष्ट्र प्रमुख विवाद है।

③ बांधों के कारण केरल जैसी बौद्ध भी  
पैदा हो सकती है।

④ बांधों के कारण विकास प्रेरित विस्थापन भी  
बामने आता है।

निष्कर्षतः प्रस्तुत विधेयक के  
अनुसार बांधों से संबंधित विनाओं का समाधान  
कर बांधों के कारण में परिवर्तित किया जा  
सकता है।

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

8. जहाँ कृषि निर्यात नीति, 2018 द्वारा प्रदत्त लाभ अनगिनत हैं, वहीं वांछित परिणामों की प्राप्ति के लिये विशिष्ट चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता है। परीक्षण कीजिये। (150 शब्द) 10

While the benefits offered by Agriculture Export Policy 2018 are numerous, achievement of desired results requires certain challenges to be addressed. Examine. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

भारत द्वारा 2022 तक कृषि निर्यात को \$30 बिलियन से बढ़ाकर \$60 बिलियन व आगे \$100 बिलियन करने के लिए कृषि निर्यात नीति की बोरिंग की है।

नाम व पद

- 1) कृषि निर्यात को दोगुना करने से 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की बात की गई है।
- 2) इसमें प्रमाणीकरण व्यवस्था की बात की गई है। अतः जैविक पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
- 3) इस नीति में छेड़-खराबों के दिनों उत्सव-वध की बात की गई है अतः राज्यों की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा।
- 4) 60 कृषि निर्यात के लिए एकीकृत संरचना के विकास से कृषकों को अधिक लाभ मिलेगा।
- 5) निर्यात पर लगने वाले सैनेटरी व फाइटो सैनेटरी अवरोधों के नियंत्रण की बात की गई है।
- 6) इस नीति में प्रसंस्करण अवसंरचना विकास के कारण रोजगार व निवेश में बढ़ोतरी होगी।
- 7) इस योजना के कारक भारतीय निर्यात की

विविधता प्राप्त होगी।

चुनौतियाँ

- ① खाद्य प्रसंस्करण प्रवर्धन के विकास के लिए वित्त व तकनीक की कमी।
- ② भारतीय उत्पादों के प्रमाणीकरण की विकेंद्रित व्यवस्था का अभाव।
- ③ खाद्य सुरक्षा व निर्यात में समन्वय का अभाव।
- ④ वर्तमान कृषि सचिव व मंत्री श्री प्रमुख चुनौतियों में से एक हैं।
- ⑤ पशुओं के कारण भारतीय उत्पाद मंहगे लगे जाते हैं।

मिल्कपैना किसानों व अर्थ व्यवस्था के लाभ के लिए कृषि निर्यात नीति 2018 के समस्त विद्यमान चुनौतियों का समाधान किया जाना आवश्यक है।

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

9. हाल ही में अमेरिका ने सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (जी.एस.पी.) के अंतर्गत भारतीय निर्यात को दी जाने वाली वरीयता को वापस ले लिया है। इस संदर्भ में सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली की अवधारणा की व्याख्या करते हुए भारत पर इस वापसी के प्रभाव की चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

Recently, the US has withdrawn its preferential treatment to Indian exports under the Generalized System of Preferences (GSP). In this context, while explaining the concept of Generalized System of Preferences, discuss the impact of withdrawal on India.

(150 words) 10

अमेरिका द्वारा "अमेरिका फस्टि" नीति व व्यापार युद्ध के माध्यम से कार्य करते हुए ~~व्यापार युद्ध~~ पर संरक्षणवादी उपायों पर बल दिया जा रहा है।

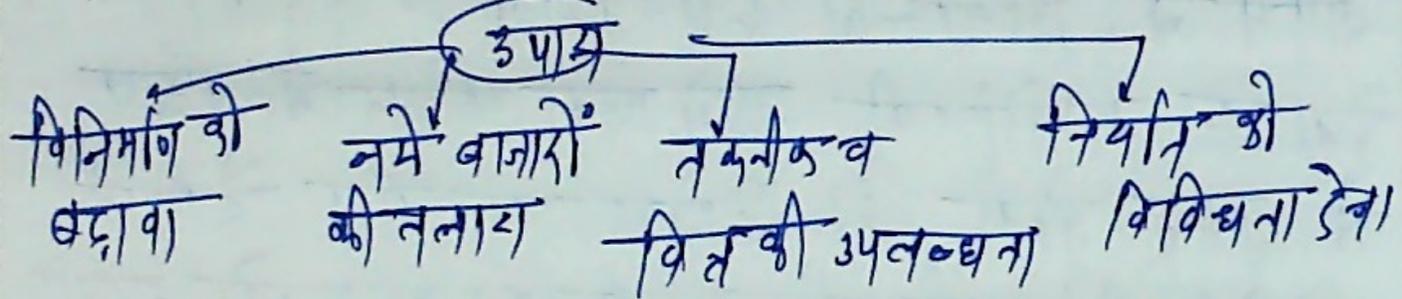
इसी क्रम में अमेरिका द्वारा भारत से ~~दिए~~ सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली की वरीयता को वापस ले लिया है। इस प्रणाली के तहत किसी देश के उत्पादों की अमेरिकी बाजार में पहुँच में वृद्धि होती है। ऐरिफ व नॉन ऐरिफ अवरोधों में कमी की जाती है या उनको हटा लिया जाता है।

वर्तमान में भारत के लगभग 60 उत्पादों को इस प्रणाली का लाभ मिल रहा था। यह वरीयता विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अंतर्गत सकारात्मक विमोड के माध्यम से दी जाती है।

प्रभाव

① भारतीय उत्पादों की अमेरिकी बाजार में पहुँच बाधित होगी क्योंकि इसकी लागत में कमी आयेगी।

- ① भारत - अमेरिका व्यापार में कमी आयेगी जो वर्तमान में \$75 बिलियन के लगभग है।
- ② भारत को वियतनाम व चीन से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा।
- ③ इस पुणानी के कारण भारत के विदेशी मुद्रा भण्डार में कमी आयेगी जो भारत के चार खता घाटे में वृद्धि का कारण बन सकता है।
- ④ भारत - अमेरिका ~~के~~ संबंधों के अन्य क्षेत्र भी प्रभावित होंगे।



निष्कर्षतः अमेरिका के साथ वास्तविक में साथ-साथ अन्य नैकालिक उपायों के माध्यम से भारतीय बिक्री के संरक्षण का प्रयास किया जाना चाहिए।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

10.

बंदरगाह अपने शहर और राज्य के लिये महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ उत्पन्न करते हैं। परीक्षण कीजिये।

(150 शब्द) 10

Ports create significant economic payoffs for their city and state. Examine.

(150 words) 10

भारत में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए सागरमाला परियोजना को बढ़ावा दिया जा रहा है जो बंदरगाहों के लाभों पर आधारित है।

लाभ

① बंदरगाह विपत्त का क्षति विकास उपलब्ध बनता है तथा उस राज्य की विपत्त पर चुंगी भी प्राप्त होती है।

② बंदरगाह विकास के कारण रोजगार का वृद्धि भी होता है क्योंकि उस क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र व निवेश को बढ़ावा दिया जाता है।

③ बंदरगाह उस समुदाय के विकास पर भी बल देता है। इसी कारण महाराष्ट्र, गुजरात व वनारस का तटीय समुदाय अधिक सशक्त है।

④ बंदरगाह के कारण आंतरिक क्षेत्र से बने मालों को बढ़ावा मिलता है।

⑤ बंदरगाह के कारण नीली क्रांति की सम्भावनाओं का भी दोहन किया जा सकता है।

⑥ बंदरगाह आधारित विकास उस शहर में आपूर्ति सृष्टि के संबंध में सहायक होता है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

① बंदरगाहों के विकास के कारण कृषि व अन्य सम्बंधित  
उत्पादों की पहुँच में वृद्धि होगी है।

② बंदरगाह के कारण आवासीय क्षेत्र का विकास  
होना है जो राज्य व शहर के लिए  
सिल-ओवर इफेक्ट का कार्य करता है।

इसी कारण सरकार द्वारा  
विशेष आर्थिक क्षेत्र सागरमाला, तटीय आर्थिक  
क्षेत्र व विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जा  
रहा है।

निष्कर्षतः बंदरगाह आधारित व विदेशी  
आधार में विकास के साथ-साथ शहर व राज्य  
के विकास में भी सहायक होता है।

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

11.

सड़क क्षेत्र भारत में यात्रियों एवं माल ढुलाई दोनों की आवाजाही का सबसे बड़ा हिस्सा साझा करता है। भारत में सतही परिवहन के विकास में निहित चुनौतियों का परीक्षण कीजिये तथा इन चुनौतियों के समाधान हेतु उपाय सुझाईये। (250 शब्द) 15

The road sector in India accounts for the largest share in the movement of both passengers and freight. Examine the challenges and suggest measures for development of surface transport in India. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

भारत में सड़क परिवहन यात्रियों व माल ढुलाई का सबसे बड़ा साधन है जो वर्तमान में कई समस्याओं से ग्रसित है।

वर्तमान में राष्ट्रीय व राज्य मार्गों के माध्यम से माल की ढुलाई की जाती है। साथ ही सड़क अवसंरचना की पद्धति में वृद्धि, रेलवे अवसंरचना की सीमितता व त्वरित परिवहन की लागत के कारण वर्तमान में भी यह परिवहन का सबसे बड़ा माध्यम है।

शहरी व ग्रामीण जनसंख्या के मध्य भौगोलिक गतिविधियों व परिवहन व्यवस्था का संभालन सड़क के माध्यम से ही किया जाता है। सड़क एवं राजमार्गों में माल पर द्वारा भी इस तथ्य को उजागर किया है। लेकिन परिवहन का यह माध्यम से धीमा व महंगा होता है। साथ ही अवसंरचनात्मक कमी के कारण ग्राम व माल का नुकसान भी अधिक होता है।

इसी कारण परिवहन के

अन्य साधनों पर भी ध्यान दिया जा रहा है।  
चुनौतियाँ

- ① सरकार के पास एवं वित्त की कमी के कारण अवसंरचना विकास की गति धीमी है।
- ② PPP मॉडल में पर्यावरणीय व विभागीय अनुमोदनों में देरी के कारण लागत में वृद्धि हो रही है।
- ③ सड़कों पर निमित्त बाधाओं (येल) के कारण समय व लागत में बढ़ोतरी होती है।
- ④ ग्रामीण स्तर तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी का प्रभाव देखा जाता है।
- ⑤ साथ ही मारतीय सड़कों की गुणवत्ता में कमी के कारण दुर्घटनाओं में भी अधिकता होती है।
- ⑥ वैबिंग व्यवस्था में कमजोरी के कारण पवित्रीय पहलुओं में कमी जा रही है।

समाधान

- ① रोड प्रसेसमेंट प्रोग्राम के माध्यम से सड़क अवसंरचना में गुणवत्ता का समावेश।
- ② BS-11 के माध्यम से गति व पर्यावरणीय पहलुओं पर ध्यान देना।
- ③ PPP निर्माण के लाइव्रेड एन्वुटि मॉडल

~~उसाध-साध पर्यावरणीय मंजूरीयों में सरकार की भूमिका हो।~~

~~(4) कित्त व तकनीक के लिए निजी क्षेत्र उसाध सतयोग तथा परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाना चाहिए।~~

~~(5) ई-वे बिल अवस्था को उभावी रूप से लागू राना तथा डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना।~~

~~(6) प्रकीकृत परिवहन व्यवस्था (जलमार्ग, रेल व सड़क) का विकास।~~

~~निष्कर्षतः सड़क परिवहन के साथ-साथ अन्य विकल्पों के माध्यम से परिवहन व्यवस्था में क्रांति लाई जा सकती है।~~

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

12. भारत में हम लंबे समय से रोजगार-विहीन संवृद्धि के संकट का सामना कर रहे हैं, परंतु वर्तमान में देश के समक्ष बड़ी चुनौती बेरोजगारी के बजाय अल्प-रोजगार है। सुस्पष्ट कीजिये। (250 शब्द) 15

Since long, we are facing the crisis of jobless growth in India, but the bigger challenge that presently the country faces is underemployment rather than unemployment. Elucidate. (250 words) 15

नीति आयोग तथा आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के द्वारा भारत में रोजगार विहीन संवृद्धि के बजाय अल्प रोजगार को बड़ी समस्या माना है।

हमारी आर्थिक संरचना का टॉप दोगुना होने के कारण विनिमय क्षेत्र विकास नहीं हुआ तो सेवा व कृषि क्षेत्र में रोजगार की सम्भावनाओं में कमी आ रही है इस कारण भारत में आर्थिक संवृद्धि व बेरोजगारी साथ-साथ बढ़ रही है जो रोजगारविहीन संवृद्धि का सूचक है।

यह कारण जनोपयोगी कामों का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया तथा भूमिगत के संरचनात्मक परिवर्तन में बाधा बनी हुई है।

भावधिक रोजगार सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान में रोजगार के बजाय अल्परोजगार की बाधा है।

① वर्तमान में बढ़ती शिक्षा के कारण ऐच्छिक बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

② परिवार की आय में वृद्धि के कारण महिलाओं में कार्य करने की पहल में कमी आयी है जो उनमें शिक्षा का स्तर भी बढ़ा है।

इसरी तरफ अल्परोजगार की समस्या अधिक मयानक है-

① अल्परोजगार के कारण अर्थव्यवस्था के ~~संरचनात्मक~~ परिवर्तन में बाधा बनी हुई है।

② अल्परोजगार के कारण जनांकिकीय लाभों का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है।

③ अल्प रोजगार के कारण आय में कमी, पूँजी निर्माण में बाधा के कारण आर्थिक संवृद्धि की दर में कमी आ रही है।

④ अल्प रोजगार के कारण सरकार को बेरोजगारी के सभी आँकड़ों का ज्ञान नहीं हो पाता है।

⑤ अल्प रोजगार तकनीक व वित्त की प्राप्ति में भी बाधक है।

⑥ अल्प रोजगार के कारण सामाजिक सुरक्षा योजनाओं व अन्य सुधारों को लागू करने में भी बाधा आ रही है।

⑦ अल्प रोजगार के कारण मानवीय संसाधनों का कुशल उपयोग नहीं हो पा रहा है तथा ग्रामीण व्यक्ति आय में प्राप्त वृद्धि नहीं कर पाते।

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

उपाय

- ① शिक्षा व्यवस्था में सुधार व गवाचारी सांस्कृतिकों के बढ़ावा।
- ② फौजदारी विकास के माध्यम से रोजगार सृजन का
- ③ विदेशी निवेश व तकनीक के लिए व्यवसाय की सुगमता में वृद्धि
- ④ योजनाओं को समेकित रूप से लागू करना तथा मांग आधारित प्रशिक्षण।

निष्कर्षतः वर्तमान संवेचनात्मक मंती से वास्तव चिकित्से तथा त्वरित विकास के लिए रोजगार सृजन व अल्परोजगार की समाप्ति को दूर करने की आवश्यकता है।

13.

भारत में नीली क्रांति की संभाव्यता तथा चुनौतियों का उल्लेख कीजिये।

(250 शब्द) 15

Highlight the potential and challenges of Blue Revolution in India.

(250 words) 15

नीली क्रांति समुद्री संसाधनों का मानवीय उपयोग की दृष्टि से प्रसंस्करण व प्रबंधन करने से संबंधित है।

भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ही नीली क्रांति पर ध्यान दिया गया लेकिन भारत अभी भी इसका दोहन नहीं कर पाया है।

नीली क्रांति की सम्भावना

① भारत मत्स्य उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान पर है।

② सरकार द्वारा त्रिनीप कुमार व मीना समिति का निर्माण मत्स्य की सम्भावना के दोहन के लिए किया है।

③ सरकार द्वारा डीप ओशन मिशन व मत्स्य पर नीति निर्माण के माध्यम से सक्रिय सहयोग दिया है।

④ प्रधानमंत्री सम्पदा योजना, सागरमाला योजना के माध्यम से अवसरानुसार काम निर्माण किया जा रहा है।

⑤ भारत में विशाल जनसंख्या की बाध व

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

- पोषण सुरक्षा के लिए यह उपयोगी है
- ⑥ भारत के पास विशाल तट रेखा है
  - ⑦ नीली क्रांति तेल व गैस के माध्यम से
  - भारत की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान का सपना है
  - ⑧ नीली क्रांति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा निवेश पर कल रिया जा रहा है
- चुनौतियाँ
- ① नीली क्रांति की सम्भावना के दोहन के लिए तकनीक व विदेश निवेश की कमी है
  - ② केन्द्र व राज्यों के मध्य समन्वय का अभाव भी संसाधनों के पुर्वचन में बाधा है
  - ③ भारतीय जलवायु (उष्णकटिबंधीय) के कारण समुद्री जीवों में वसा अधिक होती है तथा इस कारण इनकी उपयोगिता सीमित हो जाती है
  - ④ सामाजिक व सांस्कृतिक कारणों से भी मत्स्यन का पूर्ण उपयोग नहीं किया जाता
  - ⑤ समुद्री सुरक्षा की नीली क्रांति के समक्ष एक प्रमुख बाधा है
  - ⑥ वर्तमान में समुद्री पादितंत्र प्रभावित है तथा तेल व गैस अन्वेषण के कारण यह और अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।  
(Candidate must not write on this margin)

⑥ नीली क्रांति के लिए आवश्यक अवसरचना, कनेक्टिविटी व निर्णय नीति का अभाव है।

निष्कषीत। रोजगार व खाद्य व ऊर्जा सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से नीली क्रांति की सम्भावनाओं का सतत उपयोग किया जाना चाहिए।

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

14. गरीबी दूर करने के क्रम में नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये कई योजनाएँ शुरू की गई हैं। इनके वांछित परिणाम क्यों नहीं प्राप्त हुए हैं? (250 शब्द) 15

There has been plethora of schemes for providing social security to citizen in order to address poverty. Why have they not yielded desired results? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

भारत एक कल्याणकारी राज्य है तथा संवैधानिक माफ़ी समानता व सामाजिक न्याय की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ लागू की गईं।

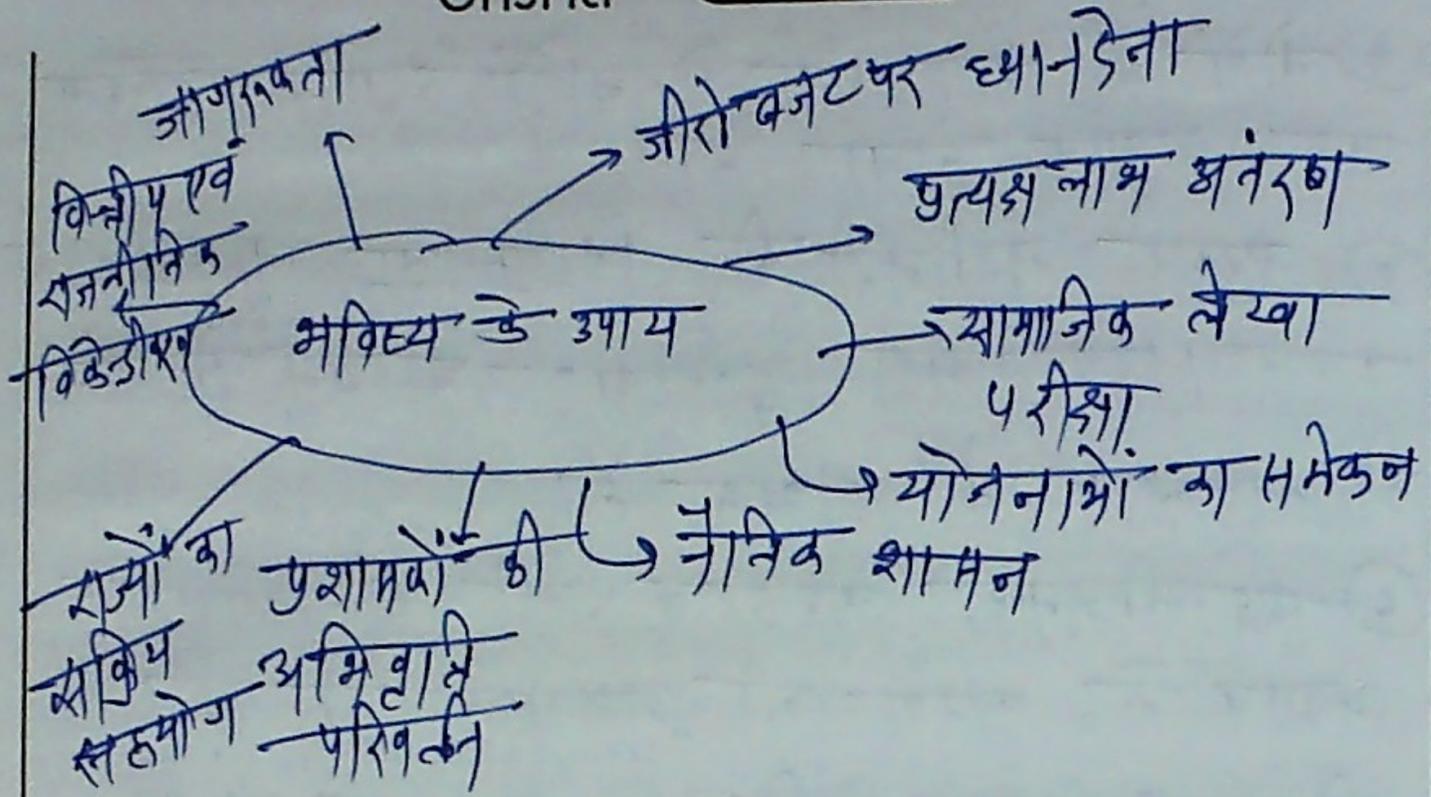
योजना

- ① पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य गरीबी निवारण तथा सामाजिक सुरक्षा था।
- ② राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम तथा भूरेगा भी इसी दिशा में एक उपक्रम हैं।
- ③ श्रम पेंशन योजना, सार्वजनिक कितरण व्यवस्था, अन्य पेंशन योजनाएँ।
- ④ साथ ही राज्यों द्वारा भी कई योजनाओं का निर्माण किया गया है यथा आमादास योजना।  
वांछित सफलता क्यों नहीं
- ① योजनाओं में श्रद्धिकता के कारण कई योजनाएँ अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुईं।
- ② योजनाओं का निर्माण टॉप डाउन एप्रोच के आधार पर किया गया।
- ③ योजनाओं के लाभार्थियों के चयन व लाभ कितरण में अनियमितता थी।

- ④ लोगों में काष्णकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता का अभाव होता है।
- ⑤ सरकारी मशीनरी की निष्क्रियता, बालकी भाषा व पथास्थानिवादी दृष्टिकोण से इन योजनाओं की सफलता में बाधक है।
- ⑥ कई योजनाएँ केन्द्र व राज्यों के सहयोग के अभाव के कारण ही असफल हो गयीं। किसान सम्मान निधि व क्षुपुष्यान भारत योजना की सफलता में भी केन्द्र-राज्य सहयोग प्रमुख बाधा है।
- ⑦ योजनाओं का निर्माण वांग अन्धारित दृष्टिकोण के बजाय सरकारी केहीकृत दृष्टि से किया जाता रहा है।
- ⑧ सामाजिक लेखा परीक्षा, तकनीकी प्रयोग के अभाव के कारण योजनाओं की महयावाधि समीक्षा का अभाव रहा है।
- ⑨ गरीबी निवारण की विभिन्न योजनाओं के लिए फण्ड का समय पर आवंल नही किया गया तो वित्रीय व राजनीतिक विडेहीकरण के अभाव में ग्राम सभाओं को इन योजनाओं में शामिल नहीं किया गया।

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)



उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

निष्कर्ष: सतत विकास लक्ष्यों  
की प्राप्ति एवं 2022 तक गरीब भारत के  
निर्माण के लिए योजनाओं के समेकन  
विद्यमान चुनौतियों का समाधान आवश्यक है।

15.

हाल ही में दूरसंचार विभाग ने भारत में मोबाइल ऑपरेटरों को 5जी परीक्षण शुरू करने की अनुमति प्रदान की है। 5जी के क्या लाभ हैं और इसके समक्ष चुनौतियों को गिनाइये। (250 शब्द) 15

Department of Telecommunication has recently allowed mobile operators in India to start 5G trials. What are the advantages of 5G and enumerate the challenges ahead of it. (250 words) 15

भारत में 5G तकनीक की व्यवहार्यता के लिए पॉल एम्पलवाई समिति का गठन किया गया तथा सरकार के सहयोग से इस क्षेत्र में परीक्षण भी किये जा रहे हैं।

5G संचार की एक नवीन तकनीक है जो रेडियो तरंगों के तीव्र गति के संचरण के साथ-साथ सुरक्षा का भी ध्यान रखती है।

लाभ

① लो लेटेंसी दर होने के कारण 5G की भविष्य की तकनीक मानी जा रही है।

② 5G, 4G की तुलना में 100 गुना अधिक तीव्रता से डाटा का संचरण कर सकती है।

③ 5G के माध्यम से संचार सम्बन्धन भी द्रवी बढ़ जायेगी।

④ 5G औद्योगिक क्रांति 4.0 के लिए एक आवश्यक घटक है।

⑤ 5G से रोजगार का सृजन होगा तथा एक नया आधुनिक समाज का निर्माण होगा।

⑥ 5G परियोजना प्रोकारल क्रांति व सरकारी डेटा सम्बन्धन में तीव्रता लायेगी तथा विश्वी

प्रिये में वृद्धि होगी

① 5G के कारण भारत में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के क्रियान्वयन में भी सहायता मिलेगी।

समस्य चुनौतियाँ

- ① भारत में अभी तक ग्रामीण क्षेत्र में 4G की पहुँच नहीं है यहाँ 5G अभी दूर की बात है।
- ② 5G के लिए अवसरानुसार की आवश्यकता होगी जो सार्वजनिक खर्च को बढ़ावा देगा।
- ③ 5G के कारण डेटा चोरी की घटना भी बढ़ जाएगी क्योंकि वर्तमान डेटा संरक्षण उपाय अप्रभावी हो जाएंगे।
- ④ 5G के कारण ग्रामीण व शहरी विषमता में और अधिक बढ़ोतरी होगी।
- ⑤ 5G के लिए प्रिये के कारण बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं पर दबाव आएगा जो अभी बैंक की स्थिति में है।
- ⑥ 5G को लेकर अभी लोगों में जागरूकता का अभाव है।
- ⑦ 5G के लिए भारत को तकनीक की आवश्यकता होगी जो भारत के पास नहीं है।

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।  
(Candidate must not  
write on this margin)

भारत को 5G के नामों ज्ञान आधारित समाज, डिजिटल इण्डिया की सफलता व डेटा सम्प्रेषण तीव्रता के लिए 5G PPP मॉडल पर कार्य करते हुए तकनीक, कितने एवं अनुसंधान पर ध्यान देकर मानकों का निर्धारण करना चाहिए।

निष्कर्ष: 5G अण्डिया की तकनीक है अतः विभिन्न उपायों के माध्यम से भारत इस क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व कर सकना है।

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

16.

विश्व भर के महासागरों में माइक्रोप्लास्टिक एक नया संकट बन कर उभरा है। माइक्रोप्लास्टिक क्या है, इसके स्रोत तथा इस संकट से निपटने के लिये संभावित उपाय क्या हैं? (250 शब्द) 15

Microplastic has become a new menace in oceans around the world. Explain what are microplastics, their sources and possible measures to counter this menace.

(250 words) 15

मानवीय हस्तक्षेप के कारण समुद्र भी परिकूल रूप से प्रभावित हो रहे हैं तथा इनमें जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण व माइक्रोप्लास्टिक शामिल है।

माइक्रोप्लास्टिक माइक्रोप्लास्टिक के छोटे आकार के कारण हैं जो आकार में अत्यंत छोटे होते हैं तथा समुद्री ~~पर्यावरण~~ पर्यावरण व इनके स्वास्थ्य को परिकूल रूप से प्रभावित करता है।  
नया संकट क्यों?

- ① माइक्रोप्लास्टिक का प्रयोग जीवन के सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। इस कारण इस पर नियंत्रण कठिन है।
- ② माइक्रोप्लास्टिक जैव संयोजन व जैव आवर्धन के कारण जीवों को परिकूल रूप से दीर्घकाल तक प्रभावित करते हैं।
- ③ माइक्रोप्लास्टिक पर नियंत्रण बढ़ा कठिन है तथा इसके स्रोतों की पहचान संभव ~~है~~ मुश्किल है।
- ④ माइक्रोप्लास्टिक जीव के माध्यम से मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहा है।
- ⑤ माइक्रोप्लास्टिक पर नियंत्रण व इसके प्रभाव को

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

कम करने की उम्मीद नहीं है।

(ज्ञान)

- ① माइक्रोप्लास्टिक फेशवास, साबुन व अन्य कॉस्मेटिक में प्रयोग किया जाता है।
- ② माइक्रोप्लास्टिक खाद्य पदार्थों व औद्योगिक अपशिष्ट से भी पैदा होता है।
- ③ माइक्रोप्लास्टिक का उत्पादन वस्त्र उद्योग, रसायन व कीटनाशक उद्योग भी है।
- ④ माइक्रोप्लास्टिक का बड़ा स्रोत पेट्रोलियम रिफाइनरी, प्लास्टिक उत्पाद है।
- ⑤ माइक्रोप्लास्टिक हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। इस कारण इसके स्रोत भी विस्तारित हैं।

(उपाय)

- ① ग्लोबल यूज प्लास्टिक पर 2022 तक नियंत्रण बनाने के लक्ष्य का क्रियान्वयन।
- ② औद्योगिक क्षेत्रों में अपशिष्ट निपटण की तकनीक का अन्नयन व समुद्रों में अपशिष्ट निपटण पर नियंत्रण।
- ③ समुद्री जीवों में माइक्रोप्लास्टिक की प्रभावी निगरानी तथा समय पूर्व उपायों पर ध्यान देना।
- ④ दैनिक जीवन के उत्पादों (कॉस्मेटिक) की

उम्मीदवार को इस  
हार्शिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

अन्य प्रकार की सहयोगी उत्पादों से प्रतिस्थापित करना।

⑤ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से माइक्रोप्लास्टिक के लिए मानकों का निर्धारण व 50 माइक्रोन से कम आकार की प्लास्टिक के उत्पादन पर नियंत्रण

⑥ कृषि क्षेत्र में परम्परागत इनपुटों को बढ़ावा तथा सुपोषण की क्रिया पर नियंत्रण।

निष्कर्षतः समूह व मानवीय जीवन के संरक्षण के लिए माइक्रोप्लास्टिक पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से नियंत्रण किया जाना चाहिए।

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

17.

भारत भूमि क्षरण एवं मरुस्थलीकरण के मुद्दे से निपटने के लिये वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (यू.एन.सी.सी.डी.) के पक्षकारों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत में भूमि क्षरण एवं मरुस्थलीकरण के क्या कारण हैं और इन्हें किस प्रकार हल किया जाना चाहिये? (250 शब्द) 15

India will host a session of the Conference of Parties to United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) in 2019 to address the issue of land degradation and desertification. What are the reasons of land degradation and desertification in India and how to deal with it? (250 words) 15

यू.एन.सी.सी.डी. ने 2030 तक लैंड रिजिनेशन  
यूटिलिटी का लक्ष्य निर्धारित किया है तथा  
भारत भी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए  
रहा है।

वर्तमान में मानवीय एवं प्राकृतिक कारणों से  
भूमि का लगातार क्षरण हो रहा है तथा इसमें  
मानवीय कारणों की भूमिका लगातार बढ़ती जा  
रही है। भारत भी इस समस्या से जूझ रहा है  
तथा भारत की भूमि भी क्षरण का सामना कर  
रही है।

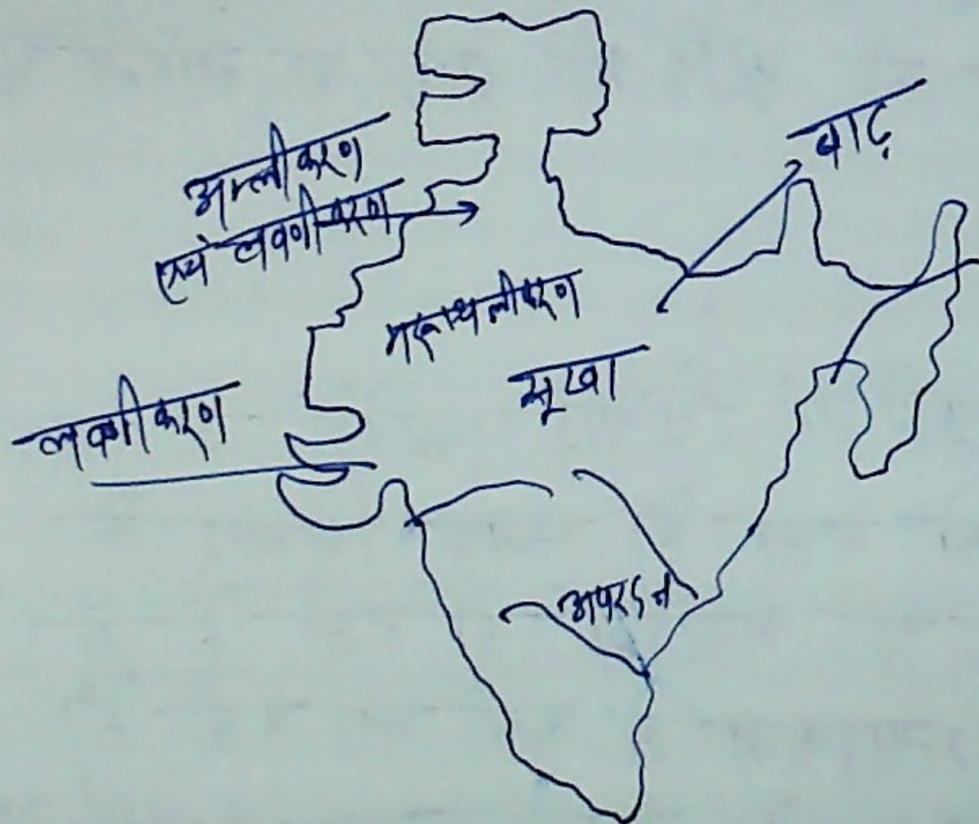
कारण

- 1) भौतिक कृषि एवं सिंचाई पद्धतियों के कारण  
भूमि क्षरण हो रहा है। पनडू सिंचाई के  
कारण भूमि का अपरदन हो रहा है।  
एकल कृषि उत्पादकता में कमी ला रही है।
- 2) कृषि में बढ़ते कीटनाशक तथा अपशिष्टों  
के विपदान की अचित व्यवस्था का अभाव भी  
भूमि क्षरण का कारण है।

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

- ⑥ बाढ़ एवं सूखे के कारण भूमि का क्षरण हो रहा है।
- ⑦ खनन एवं औद्योगिक गतिविधियों के उत्सर्जन के कारण भूमि की उत्पादकता में लगातार कमी आ रही है।
- ⑧ वनों की लगातार कटाई व अनियंत्रित पशु चरण के कारण मरुस्थल व उष्ण हो रहा है।
- ⑨ भूमि क्षरण एवं मरुस्थलीकरण के लिए भूमिगत जल का अतिरोहन, जल अभाव व अग्नीकरण, लवणीकरण भी जिम्मेदार है।
- ⑩ मानवीय गतिविधियों के कारण आर्द्र भूमि तथा पीटलैंड का भी क्षरण हो रहा है।



उपाय

- ① भूमि का वैज्ञानिक उपाय, परम्परागत कृषि-औद्योगिक कृषि के साथ-साथ केवल चक्रण पर बल।

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

- ② जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (2008) को प्रभावी रूप से लागू करना।
- ③ इजरायल सहयोग से सूक्ष्म सिंचनी को बढ़ावा देना।
- ④ नदी जोड़ने योजना के माध्यम से बाढ़ व सूखा की समस्या का समाधान।
- ⑤ औद्योगिक अपशिष्ट निपटान की अचिर अवस्था तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड व अन्य योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करना।
- ⑥ मरुस्थल में वनों को लगाना तथा नियंत्रित पशुचारण पर बल।
- ⑦ अंतरराष्ट्रीय सहयोग व 2030 तक LDCN कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू करना।

निष्कर्षतः कृषि व जल संसाधनों के संरक्षण के साथ-साथ भूमि उपजावत को बढ़ावा देने के लिए बहुआयामी समाधानों की आवश्यकता है।

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

18.

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एन.डी.एम.पी.) आपदा प्रबंधन चक्र के सभी चरणों के लिये सरकारी एजेंसियों को एक रूपरेखा तथा दिशा-निर्देश प्रदान करती है। सुस्पष्ट कीजिये। (250 शब्द) 15

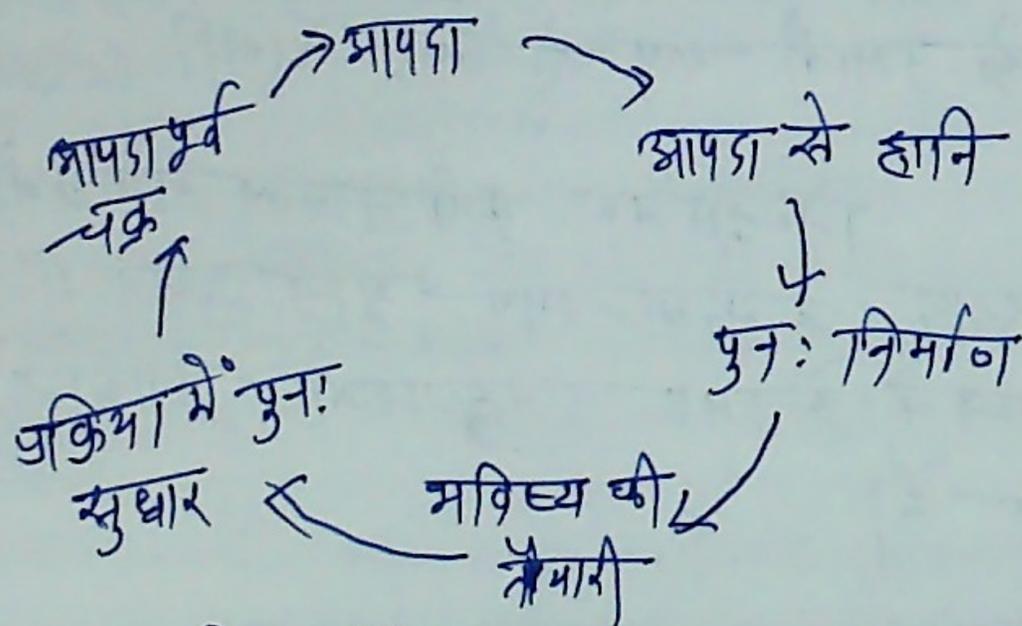
The National Disaster Management Plan (NDMP) provides a framework and direction to the government agencies for all phases of disaster management cycle. Elucidate. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

सेंजर्स फ्रेमवर्क के छाने-पनिबद्धता दर्शाने व आपदा प्रबंधन के सुस्पष्ट टाँचे का निर्माण करने के लिए 2016 में 3 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई।

यह योजना सेजर्स फ्रेमवर्क के चार उद्देश्यों को भी शामिल करती है जो आपदा प्रबंधन के प्रत्येक चक्र पर प्रभावी कार्यवाही का भी वर्णन करती है।



रूपरेखा व दिशा निर्देश

① इसके तहत आपदा के अद्ययन, आपदा प्रबंधन में सुधार, संस्थागत व गैर-संस्थागत उपायों से आपदा प्रबंधन में निवेश बढ़ाना तथा अविवेक की तैयारी के बारे में बताया गया है।

② आपदा प्रबंधन योजना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आपदा पूर्व चक्र के बारे में बतानी है। इसके तहत पुरानी आपदा के कारणों व प्रभावों का अध्ययन करने के साथ-साथ अधिकारियों के नेतृत्व पर भी बल देनी है।

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

③ यह योजना बतानी है कि केन्द्र व राज्यों के मध्य आपदा पूर्व चक्र में सहयोग के माध्यम से किस प्रकार कार्य किया जाना चाहिए।

④ यह योजना आपदा के दौरान अधिकारियों की त्वरित प्रतिक्रिया व जन सहभागिता आधारित आपदा प्रबंधन चक्र पर बल देती है।

⑤ आपदा क्वाक में अधिकारियों के निरूपण के लिए दिशा निर्देश व रूपरेखा का निर्माण किया गया है।

⑥ योजना बतानी है कि आपदा पहचान प्रक्रिया निर्माण व लोगों के पुनर्वास के लिए अधिकारियों को किस प्रकार कार्य किया जाना चाहिए।

⑦ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कर्मचारियों के प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण व नवीन तकनीकों के अपनाने पर भी बल देती है।

⑧ इस योजना के तहत आपदा के लिए प्रभावी चेतावनी प्रणाली, अधिकारियों के मध्य समन्वय

~~तथा पारदर्शिता व जवाबदेही का निर्धारण किया गया है।~~

~~व्यवहार में इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं किया जाता तथा विभिन्न अधिकारियों के मध्य समन्वय का अभाव रहता है तथा सूचना प्रवृत्ति भी बाधित रहती है।~~

~~निष्कर्षतः आपदा प्रबंधन ७ में दस्ता के लिए इस योजना के दिशा निर्देशों व रूपरेखा को व्यवहार में ही क्रियान्वित किया जाना चाहिए।~~

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।  
(Candidate must not write on this margin)

19. हाल के वर्षों में हुए डेटा विस्फोट (Explosion) ने समाज को कई गुना लाभान्वित किया है। बताइये कि साझा की गई सूचना को सार्वजनिक संपत्ति के समान क्यों माना जाता है? (250 शब्द) 15

Concurrent with the data explosion of recent years, its benefit to society has increased manifold. Explain why shared data be treated as a public good? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

माना जा रहा है कि 21 वीं सदी डेटा की सदी है  
नया डेटा 21 वीं सदी का नेतृ है जो राजनीतिक  
हाथ से भी महत्वपूर्ण है।

वर्तमान में बढ़ते ऑनलाइन  
क्रियाकलापों के कारण डेटा विस्फोट की स्थिति उत्पन्न  
हुई है।

समाज के लाभ

① डेटा के कारण सरकारी योजनाओं का वास्तविक क्रियान्वयन  
हुआ है तथा डेटा का लाभ समाज को मिला है।  
(उदा. - प्रधानमंत्री उज्वला योजना)

② डेटा के कारण ज्ञान आधारित समाज का निर्माण हुआ  
है तथा लोगों की सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर  
अगरवता बढ़ी है।

③ डेटा के कारण महिलाएँ भी अपने अधिकारों के  
अभिप्रेत हुई हैं तथा उनके लिए रोजगार के  
अवसर पैदा हुए हैं।

④ डेटा विस्फोट के कारण वैश्वीकरण के सकारात्मक  
लाभ समाज में फैले हैं तथा कई स्वयंसेवकों पर  
प्रहार हुआ है।

⑤ डेटा के कारण बढ़ता ग्लोकलाइजेशन, डिजिटल  
भूगोल व निम्न वर्ग की चेतना भी समाज के



drishti



लिए लाभदायक है।

व्यक्तियों द्वारा साक्षात्कीर्ति सूचना को सार्वजनिक सम्पत्ति के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए -

- ① इस प्रकार सार्वजनिक सम्पत्ति के समान डेटा का संरक्षण प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व बन जाना है।
- ② सार्वजनिक सम्पत्ति के समान डेटा का उपयोग सुशासन के लिए किया जाना चाहिए।
- ③ डेटा को सार्वजनिक सम्पत्ति के रूप में मानने से सरकार का संरक्षण के प्रति उत्तरदायित्व बढ़ जाएगा।
- ④ डेटा को सार्वजनिक सम्पत्ति मानने से इसका प्रयोग रोजगार, निवेश व अन्य कई कल्याणकारी योजनाओं को नक्षेत्र करने में किया जा सकेगा।
- ⑤ डेटा को सार्वजनिक सम्पत्ति मानने से इसके प्रयोग पर भारोपित नियंत्रणों में कमी आवेगी तथा जागरूक समाज का निर्माण किया जा सकेगा।

साथ ही सार्वजनिक सम्पत्ति मानने के अनुरूप इस पर व्यक्ति का निजी अधिकार भी होना चाहिए। निजता के अधिकार के संरक्षण को वरीयता दी जानी चाहिए। व्यक्ति की सार्वजनिक सम्पत्ति के पश्चात् ही डेटा का उपयोग सार्वजनिक सम्पत्ति के रूप में किया

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

जगत्कारिण

निष्कर्षिता बी. एन. श्रीकृष्णा समिति  
प्रकार उद्योग की शरीर में उद्योग-सांख्यिक  
सम्पत्ति होने के साथ-साथ इसका संरक्षण  
यस्य का मौलिक अधिकार ही है

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

20.

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये ई-कॉमर्स के महत्त्व की व्याख्या कीजिये। राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति मसौदा किस सीमा तक ई-कॉमर्स क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान करता है? (250 शब्द) 15

Explain the importance of e-commerce for Indian economy. To what extent does draft national e-commerce policy address the challenges of e-commerce sector? (250 words) 15

ई-कॉमर्स सूचना तकनीक पर आधारित एक विपणन तकनीक है जहाँ उपभोक्ता व विक्रेता के मध्य एक वास्तवी संबंध होता है।

वर्तमान में भारत में ई-कॉमर्स बाजार \$ 50 बिलियन के लगभग है जो कुछ समय में \$ 500 बिलियन हो जायेगी।

महत्व

- ① ई-कॉमर्स भारत में विनिर्माण-गतिविधियाँ को बढ़ावा देगा तथा रोजगार विहीन संवृद्धि की दशा से बाहर निकला जा सकेगा।
  - ② ई-कॉमर्स के कारण विदेशी निवेश में वृद्धि होगी।
  - ③ ई-कॉमर्स से सृजित उद्योग का उपयोग लासिन नीति निर्माण व नीतियों के क्रियान्वयन में किया जा सकेगा।
  - ④ ई-कॉमर्स के कारण रोजगार को बढ़ावा मिलेगा जो कचत व पूंजी निर्माण के माध्यम आर्पित संवृद्धि को बढ़ावा देगा।
  - ⑤ ई-कॉमर्स के कारण गुणवत्ता व वस्तुओं की उपलब्धता में भी सुधार होगा जिसका फायदा उपभोक्ता को मिलेगा।
- ई-कॉमर्स पर नियंत्रण करने के लिए ई-कॉमर्स मसौदा तैयार किया गया—

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

- ① इसके तहत ई-कॉमर्स को परिभाषित किया गया।
- ② इसमें उद्योग स्थानीयकरण का प्रावधान है।
- ③ ई-कॉमर्स के साथ-साथ स्थानीय व्यापारियों के हितों के संरक्षण की भी बात की गई है।
- ④ इस मसौदे में निजता के अधिकार की सुरक्षा के लिए उद्योग पर निपंत्रण की बात की गई है।
- ⑤ विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए मानकों को सरल बनाया गया।
- ⑥ सिंगल जॉइंट में निवेश पर कुछ प्रतिबंध आरोपित किये गये।

### सुझावियाँ

- ① यह मसौदा ई-कॉमर्स कंपनियों में अविश्वास पैदा करता है क्योंकि निवेश प्रावधानों में अनिश्चितता बनी हुई है।
- ② मसौदे में निजता के अधिकार (पुट्टासामी कास) के संरक्षण के पर्याप्त उपाय नहीं किये गये हैं।
- ③ ई-कॉमर्स क्षेत्र में एकाधिकार को तोड़ने के लिए भी इस मसौदे में पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई।
- ④ उद्योग स्थानीयकरण के मुद्दे पर भी ई-कॉमर्स कंपनियों व सरकार के मध्य मतभेद विद्यमान है।

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

निष्कर्षतः ई-कॉमर्स से सम्बन्धित  
समस्याओं का समाधान कर इसे निवेश, तकनीक व  
रोगीगार का माध्यम बनाया जा सकता है जहाँ  
डेटा संरक्षण पर पर्याप्त ध्यान हो।

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)